

संघीय परिषद

संघीय आर्थिक परिषद

संघीय परिषद

+संघीय परिषद 966

संघीय 29 जुलाई, 2015 संघीय परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

संघीय आर्थिक परिषद

966- जहाँ न्योब

D; k okf.kT; vKj m|ks eah ; g crkus dh dik djæsfed%

1/2 D; k fo'o 0; ki kj l æBu ds , d gky ds ifronu ds vuq kj Hkjrh dh vk; kr 0; oLFk vHk Hk cgq tfVy cuh gpZ gS

1/4 k 1/2 ; fn glk rks rRI ædkh C; kS k D; k gS vKj bl ij Hkjrh dh D; k ifrfØ; k gS

1/2 D; k l jdkj Hkjrh ds fgrk dh j {kk gsrq , d jk"Vh; cks) d l Ei fUk vf/kdkj ufr ?kks"kr djus dk fopkj j [krh gS vKj

1/2 k 1/2 ; fn glk rks bl l ædk eavc rd D; k ixfr gpZ gS

=कै

कै ; ,oam|k jk; eah 1/2 Lora iHkj 1/2

1/2 Jherh fueyk l hrje.k 1/2

(क) और (ख) जून 2015 में आयोजित भारत की व्यापार नीति समीक्षा (टी पी आर) के भाग के रूप में तैयार की गई विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भारत की आयात व्यवस्था जटिल है। तथापि, इन अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में, टीपीआर में सूचित किया गया था कि केंद्रीय और राज्य के मूल्य वर्धित करों और वस्तुओं के घरेलू उत्पादन, खपत और बिक्री के अंतर्गत उद्ग्राह्य अन्य

करों को संतुलित करने के लिए कर अधिरोपित किए जाते हैं। ये न केवल डब्ल्यूटीओ के अनुकूल हैं अपितु अधिकांश सदस्य देशों में आम तौर पर अपनाए जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि इन अंतरों को अपेक्षाकृत अधिक सरलीकृत वस्तु एवं सेवा करों (जीएसटी) की शुरुआत के साथ और भी निष्प्रभावी किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि भारत का आयात लाइसेंसिंग तंत्र मुक्त और पारदर्शी है तथा मुख्य रूप से केवल कुछ ही प्रतिबंधित मर्चों को मानव, पशु और पादप जीवन एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने की जरूरत के आधार पर प्रभावित करता है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा गठित बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी प्रबुद्ध मंडल ने अप्रैल 2015 में प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी इस समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जाँच की जा रही है।
